EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Aarav Anand

Date: 03-12-2025

Source- जनसत्ता

अमेरिकी प्रतिबंधों के असर का विश्लेषण

भारत का रूस से तेल आयात एक तिहाई घटा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत का रूसी तेल आयात लगभग एक तिहाई घट गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि दिसंबर में यह और कम होगा, क्योंकि तेल शोधन कंपनियां प्रतिबंधों से बचने के लिए वैकल्पिक स्रोतों का रुख कर रही हैं।

आंकड़ा विश्लेषण कंपनी केप्लर के अनुसार नवंबर में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात औसतन 18 लाख बैरल प्रतिदिन रहा।

केप्लर के प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रितोलिया ने कहा कि 21 नवंबर से पहले आयात 19-20 लाख बैरल प्रतिदिन के करीब था, क्योंकि खरीदार समयसीमा से पहले माल ला रहे थे। इसके बाद मात्रा कम हो गई।

ऐसा लगता है कि तेल शोधन कंपनियों ने प्रतिबंध लागू होने से पहले कच्चे तेल का भंडार बना लिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद आयात घटकर लगभग 12.7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो मासिक आधार पर 5.7 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी दर्शाता है।

पुतिन के दौरे से पहले रूसी संसद ने भारत के साथ सैन्य समझौते को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (ब्यूरो)।

रूस की संसद के निचले सदन 'ड्यूमा' ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चार-पांच दिसंबर को नई दिल्ली की राजकीय यात्रा से पहले भारत के साथ एक अहम सैन्य समझौते को को मंजूरी दे दी। दोनों सरकारों के बीच 18 फरवरी को हस्ताक्षरित सैन्य साजो सामान संबंधी सहयोग के पारस्परिक आदान-प्रदान को पिछले सप्ताह 'ड्यूमा' को भेजा गया था।

-पूरी खबर पेज 10

साइबर संजाल के समांतर जोखिम

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर मिनट कोई न कोई भारतीय साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है, जिससे बड़े वित्तीय नुकसान के साथ ही पीड़ितों को गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात भी लगता है।

रंजना मिश्रा

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। इसका प्रमाण हमें हर दिन अपने आसपास देखने को मिलता है। एक समय था जब बैंक के छोटे-से काम के लिए भी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन आज यूपीआइ की सफलता ने लेन-देन को इतना सरल और त्वरित बना दिया है कि सड़क किनारे बैठा ठेले वाला भी 'क्यूआर कोड' से भुगतान स्वीकार कर लेता है। सरकारी सेवाओं के आनलाइन वितरण और आधार-आधारित सेवाओं ने देश के हर नागरिक के जीवन को सशक्त और सरल बनाया है। यह क्रांति हमें डिजिटल रूप से सशक्त कर रही है, लेकिन इसी डिजिटल सशक्तीकरण के साथ-साथ एक स्याह पक्ष भी सामने आया है। यह है साइबर अपराध। दरअसल, आज यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि बेलगाम खतरा बन चुका है। यह हमारी मेहनत की कमाई, हमारे व्यक्तिगत डेटा और सबसे बढ़ कर, डिजिटल व्यवस्था में हमारे विश्वास की चोरी कर रहा है। आज अपराधी भौतिक दूरी की परवाह नहीं करता। वह हजारों किलोमीटर दूर बैठ कर, बिना किसी संपर्क के, लोगों के बैंक ब्योरे तक पहुंच बना लेता है। यह एक ऐसी अदृश्य लड़ाई है जहां अपराधी हमेशा तकनीक में एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं।

वर्तमान में, साइबर अपराध के तौर-तरीकों में एक अहम बदलाव आया है। अपराधी अब अपना समय जटिल साफ्टवेयर या 'फायरवाल' में घुसने में नहीं लगाते। उन्होंने सीख लिया है कि सबसे कमजोर कड़ी हमेशा 'इंसान' होता है। अपराधी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य तीन प्राथमिक भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है- डर, लालच, और तुरंत कार्रवाई। वे इन्हीं भावनाओं को निशाना बना कर लोगों को भ्रमित करते हैं, जिससे पीड़ित खुद अपनी गोपनीय जानकारी या पैसा उनके हवाले कर देता है। यह एक ऐसा तरीका है, जहां अपराधी 'मनुष्य की कमजोरी' पर ध्यान देता है। हालिया रुझानों में, जिस रणनीति ने सबसे ज्यादा दहशत पैदा की है, वह है 'डिजिटल अरेस्ट'। यह साइबर अपराधियों का नया और मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसमें अपराधी स्वयं को केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स ब्यूरो या यहां तक कि स्थानीय पुलिस के उच्चाधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे पीड़ित को वीडियो काल करते हैं, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि में अक्सर थाने या सरकारी कार्यालय जैसा दृश्य दिखाई देता है और वे वर्दी या आधिकारिक पोशाक में होते हैं। वे पीड़ित को दिखाते हैं कि उनका आधार कार्ड या बैंक खाता किसी गंभीर अपराध में फंसा हुआ है, जैसे धन शोधन, हवाला या नशीली दवाओं की तस्करी मामले में।

धमकी का यह नाटक इतना वास्तविक होता है कि अच्छे-खासे शिक्षित और समझ रखने वाले लोग भी घबरा जाते हैं। अपराधी पीड़ित को यह विश्वास दिलाते हैं कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें अपनी सारी जमा पूंजी एक 'सुरक्षित सरकारी खाते' में 'जांच के लिए' भेजनी होगी। वे भरोसा दिलाते हैं कि जांच पूरी होते ही पैसा वापस मिल जाएगा। अपराधी यह सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ित को सोचने या किसी से सलाह लेने का समय न मिले। वे लगातार वीडियो काल कर उस पर दबाव बनाए रखते हैं। इसी तीव्र दबाव और जेल जाने के डर से, लोग जीवन भर की बचत पलक झपकते ही गंवा देते हैं। साफ है कि अपराधियों ने डर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करना सीख लिया है।

दूसरी ओर, लालच का इस्तेमाल कर की जाने वाली धोखाधड़ी भी तेजी से बढ़ रही है। 'आकर्षक रिटर्न' का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग मंच और क्रिप्टोकरंसी में निवेश कराया जाता है। अक्सर लोगों को सोशल मीडिया या टेलीग्राम पर ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें 'घर बैठे काम' या 'थोड़े समय में पैसा दोगुना' करने का वादा किया जाता है। अपराधी छोटे निवेश पर शुरुआत में कुछ मुनाफा देकर पीड़ितों का भरोसा जीतते हैं। जब पीड़ित बड़ा निवेश करता है, तो अपराधी मंच बंद करके या मुनाफा निकालने की प्रक्रिया को जटिल बना कर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा, तत्काल कर्ज देने वाले फर्जी ऐप भी तेजी से फैले हैं, जो कम कागजी कार्रवाई के नाम पर लोगों के फोन का पूरा डेटा चुरा लेते हैं और फिर भयादोहन कर उनसे वसूली करते हैं। इसके अलावा, दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी-छोटी, लेकिन व्यापक धोखाधड़ी भी आम हो गई है। 'केवाईसी अपडेट करें' या 'आपका बिजली बिल बकाया है, रात दस बजे बिजली काट दी जाएगी' जैसे संदेश भेज कर लिंक पर क्लिक कराया जाता है। ऐसा करते ही या तो व्यक्तिगत डेटा चुरा लिया जाता है या पीड़ित से ओटीपी मांग कर उसके खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करवा कर पैसे निकालने की धोखाधड़ी भी आम हो गई है, जहां अपराधी पैसा भेजने के बजाय राशि प्राप्त करने का कोड भेजते हैं और अनभिज्ञ लोग पिन डाल कर पैसा गंवा देते हैं।

> तमान में, साइबर अपराध के तौर-तरीकों में एक अहम बदलाव आया है। अपराधी अब अपना समय जटिल साफ्टवेयर या 'फायरवाल' में घुसने में नहीं लगाते। उन्होंने सीख लिया है कि सबसे कमजोर कड़ी हमेशा 'इंसान' होता है। अपराधी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य तीन प्राथमिक भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है- डर, लालच, और तुरंत कार्रवाई। वे इन्हीं भावनाओं को निशाना बना कर लोगों को भ्रमित करते हैं, जिससे पीड़ित खुद अपनी गोपनीय जानकारी या पैसा उनके हवाले कर देता है। यह एक ऐसा तरीका है, जहां अपराधी 'मनुष्य की कमजोरी' पर ध्यान देता है।

इन अपराधों की प्रकृति ऐसी है कि यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। गांव का किसान जो पहली बार डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर रहा है और शहर नागरिक, दोनों ही अब जोखिम में हैं। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर मिनट कोई न कोई भारतीय साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है, जिससे भारी वित्तीय नुकसान के साथ ही पीड़ितों को गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात भी लगता है। अपनी मेहनत की कमाई अचानक खो देने का सदमा पीड़ितों को तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का शिकार बना देता है। शर्म और बदनामी के डर से कई लोग शिकायत दर्ज कराने से भी बचते हैं, जिससे अपराधियों को और बल मिलता है।

इस गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। इनमें राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 और साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शामिल हैं। भविष्य में यह चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। कृत्रिम मेधा और 'डीपफेक' तकनीक अब अपराधियों के हाथ लग रही है। एआइ किसी की आवाज या वीडियो चेहरे की हूबहू नकल तैयार कर सकता है। ऐसे में जब ठगी करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के रिश्तेदार की आवाज और चेहरे का उपयोग कर भावनात्मक मदद मांगेगा, तो सामान्य व्यक्ति के लिए सत्य और झूठ में अंतर कर पाना लगभग असंभव हो जाएगा। डीपफेक तकनीक न केवल वित्तीय धोखाधड़ी बढ़ाएगी, बल्कि यह समाज में गहरा अविश्वास और अराजकता भी पैदा कर सकती है।

साइबर सुरक्षा का मूल मंत्र सरल है- 'रुको, सोचो और पुष्टि करो।' किसी भी लिंक पर क्लिक करने या पैसा भेजने से पहले रुकें, उस संदेश के पीछे के तर्क पर सोचें और संबंधित आधिकारिक स्रोत से फोन कर पुष्टि करें। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को इन खतरों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें 1930 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी देना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। डिजिटल इंडिया तभी सुरक्षित होगा, जब हर नागरिक साइबर सुरक्षा के प्रति सजग, जिम्मेदार और शिक्षित होगा। हमें तकनीक का इस्तेमाल करना है, न कि तकनीक से डरना है। यह तभी संभव है जब हम सुरक्षित और समझदारी से डिजिटल लेन-देन करें।

विषैले कचरे की राख अब निपटारे की बाट जोह रही | **भोपाल गैस कांड** | **पीथमपुर स्थित संयंत्र में रखा गया है कचरा**

अभी भी 900 टन राख को ठिकाने लगाने की चुनौती

इंदौर, 2 दिसंबर (भाषा)।

भोपाल में बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने से 337 टन विषैले अपशिष्ट, 19 टन संदूषित मिट्टी और 2.2 टन पैकेजिंग सामग्री समेत कुल 358 टन सामग्री को इस साल जुलाई की शुरुआत में पीथमपुरा स्थित संयंत्र में भस्म किया गया था। भोपाल से यहां इस सामग्री को लाए जाने के करीब छह माह बाद इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।

भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े विषैले अपशिष्ट, मिट्टी और पैकेजिंग सामग्री को मध्य प्रदेश के पीथमपुर स्थित संयंत्र में जलाए जाने के बाद इस प्रक्रिया से उत्पन्न लगभग 900 टन राख पांच महीने बाद भी निस्तारण की बाट जोह रही है।

भोपाल में बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने से 337 टन विषैले अपशिष्ट, 19 टन संदूषित मिट्टी और 2.2 टन पैकेजिंग सामग्री समेत कुल 358 टन सामग्री को इस साल जुलाई की शुरुआत में पीथमपुरा स्थित संयंत्र में भस्म किया गया था। भोपाल से यहां इस सामग्री को लाए जाने के करीब छह माह बाद इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अपशिष्ट को वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत एक दहन संयंत्र में भस्म किया गया जिसमें चूना और अन्य सामग्रियों को मिलाया गया और इससे लगभग 900 टन राख उत्पन्न हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस राख को पीथमपुर के ही संयंत्र में निर्माणाधीन विशेष बहु परतीय विशाल गड्ढे (लैंडफिल सेल) में सुरक्षित करने की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि यह संयंत्र धार जिले के तारपुरा गांव के पास स्थित है जिसकी आबादी लगभग 20,000 है। हालांकि, लगभग दो महीने पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राख निस्तारण के लिए वैकल्पिक स्थल खोजने का निर्देश दिया था और कहा था कि मानव आबादी के पास इसका निस्तारण अस्वीकार्य है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल यह राख इस संयंत्र के 'लीक-प्रूफ स्टोरेज शेड' में सुरक्षित तौर पर रखी गई है।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिया था कि वह एक रिपोर्ट दाखिल करे जिसमें इस राख के निपटान के लिए वैकल्पिक स्थलों का उल्लेख हो। प्रदेश सरकार के अधिकारी मामले के अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए राख के निपटारे की योजना पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि, एक अधिकारी ने मंगलवार को समाचार एजेंसी को बताया कि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटारे के लिए एक निजी कंपनी को दिए गए ठेके में इस राख को पीथमपुर के संयंत्र के परिसर में विशेष तौर पर बहु परतीय 'लैंडफिल सेल' बनाकर उसके भीतर इस राख को सुरक्षित रूप से दबाने के बाद उसे ऊपर से बंद करने का काम भी शामिल है और इस निर्माण में तमाम सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस 'लैंडफिल सेल' का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने आठ अक्तूबर को पीथमपुर स्थित संयंत्र के परिसर में बनाए जा रहे 'लैंडफिल सेल' में इस राख को सुरक्षित करने का प्रस्ताव यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह (संयंत्र) ईसानी आबादी के बेहद नजदीक है।

अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच दो चरणों में होगी जनगणना

जनसत्ता विशेष

देश में जनगणना 2027' दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण की जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, जबकि दूसरे चरण की फरवरी 2027 में होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल में यह जानकारी दी है। जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनगणना दो चरणों में होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना तथा उसके बाद दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। जनगणना के दौरान जाति गणना भी होगी। विपक्ष के लगातार दबाव के बाद बिहार चुनाव से पहले अप्रैल में सरकार ने घोषणा की थी कि जनगणना के साथ जाति गणना भी कराएगी।

मंत्रालय के मुताबिक आबादी की गणना फरवरी 2027 में की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि होगी, सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके दुर्गम इलाकों को छोड़कर, जहां यह गणना सितंबर 2026 में की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 अक्तूबर 2026 की मध्यरात्रि होगी। जनगणना की प्रत्येक कवायद से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा उपयोगकर्ताओं से प्राप्त जानकारी और सुझावों के आधार पर जनगणना से संबंधित प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाता है। मंत्री के मुताबिक जनगणना का इतिहास 150 वर्षों से भी अधिक पुराना है और प्रत्येक जनगणना में पिछली जनगणनाओं के अनुभवों का ध्यान रखा जाता है। हर जनगणना से पहले सभी संबंधित हितकारकों से सुझाव लिए जाते हैं। एक अलग प्रश्न के लिखित उत्तर में, मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 30 अप्रैल को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, जनगणना में जातिवार गणना भी की जाएगी। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2027 की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा और स्व-गणना के लिए आनलाइन प्रावधान होगा।

मंत्रालय ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया है कि जनगणना प्रक्रिया के लिए किन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। इसकी प्रश्नावली बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है। तय प्रावधान के तहत जनगणना नियम 1990 के नियम 6 के तहत जनगणना प्रश्नावली या अनुसूचियां केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की उप धारा आठ की उपधारा एक में राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाती हैं।

जनगणना के दौरान प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को आमतौर पर प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाता है। 2027 की जनगणना के लिए समय सीमा पिछली जनगणना की तरह ही रखी गई है। मंत्रालय के मुताबिक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना पूरी तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचित सूची के अनुसार की जाती है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) के माध्यम से अधिसूचित किया है।

इस मामले में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अप्रैल 2025 में निर्णय लिया था कि जनगणना 2027 के साथ ही जातियों की गणना भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिए गए सरकार के जातियों की गिनती जनगणना के साथ करने के निर्णय की जानकारी दी थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दल लगातार देश में जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं।

तैयारी

जनगणना के लिए मोबाइल एप के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा और स्व-गणना के लिए आनलाइन प्रावधान होगा। पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना तथा उसके बाद दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिए गए सरकार के जातियों की गिनती जनगणना के साथ करने के निर्णय की जानकारी दी थी। कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दल लगातार देश में जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं।

पहली बार डिजिटल जनगणना

अभी तक चल ही सामान्य प्रक्रिया के दौरान अधिकारी किसी भी आवास पर जाते थे और लिखित तौर पर जानकारियां भरते थे। लेकिन पहली बार डिजिटल जनगणना के तौर पर काम किया जा रहा है। इस लिए सरकारी एजंसियों की मदद के लिए इन कोड को तैयार करने की जरूरत पड़ी है। यह आंकड़े भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल पर एक साथ उपलब्ध होंगे। दावा किया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, सरकारी संस्थाओं के पास डिजिटल आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस बार प्रश्नों की संख्या भी कम होने की संभावना जताई जा रही है। अब तक सबसे अधिक सवाल 2011 की जनगणना में आम जनता से पूछे गए थे, इन सवालों की संख्या 29 दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त हुई जनगणना में सवालों का आंकड़ा अधिकतम 23 सवालों के बीच ही दर्ज किया गया है।

पुतिन के दौरे से पहले रूस का बड़ा फैसला

रूसी संसद ने भारत के साथ सैन्य समझौते को मंजूरी दी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

रूस की संसद के निचले सदन 'ड्यूमा' ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चार-पांच दिसंबर को नई दिल्ली की राजकीय यात्रा से पहले भारत के साथ एक अहम सैन्य समझौते को मंगलवार को मंजूरी दे दी। दोनों सरकारों के बीच 18 फरवरी को हस्ताक्षरित सैन्य साजो सामान संबंधी सहयोग के पारस्परिक आदान-प्रदान (आरईएलओएस) को प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन द्वारा अनुमोदन के लिए पिछले सप्ताह 'ड्यूमा' को भेजा गया था।

'ड्यूमा' के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने सदन के पूर्ण अधिवेशन में कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं तथा हम उन्हें महत्त्व देते हैं। हम समझते हैं कि आज समझौते को मंजूरी निश्चित रूप से हमारे संबंधों के विस्तार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आरईएलओएस समझौता यह तय करता है कि रूस और भारत एक-दूसरे के यहां सैन्य टुकड़ियां, युद्धपोत और सैन्य विमान कैसे भेजेंगे, और उनके बीच सैन्य साजो सामान सहायता किस तरह प्रदान की जाएगी। यह समझौता न केवल सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती को नियंत्रित करेगा, बल्कि उनकी साजो सामान संबंधी व्यवस्थाओं को भी तय करेगा।

रूस भारी व्यापार घाटे पर भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार: पेसकोव

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले मास्को ने कहा कि रूस को भारी व्यापार घाटे को लेकर नई दिल्ली की चिंताओं की पूरी जानकारी है। मास्को इस 'समस्या' को दूर करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह जानकारी मंगलवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने दी। पेसकोव ने भारतीय पत्रकारों के लिए आयोजित एक आनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की, जिनमें यूक्रेन में अमेरिकी शांति योजना, रूसी कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध और भारत को रूसी रक्षा मंच एवं प्रौद्योगिकी की आपूर्ति शामिल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चार और पांच दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली यात्रा से पहले एक पूर्वावलोकन के तौर पर आयोजित की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करना है।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व दो वर्षों से 18 फीसद पर स्थिर | रपट | एनएसई पर सूचीबद्ध 1,386 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण

बावन फीसद कंपनियों में महिला कर्मचारी 10% से भी कम

मुंबई, 2 दिसंबर (भाषा)।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद एनएसई में सूचीबद्ध आधे से अधिक कंपनियों में कार्यरत महिलाओं की संख्या अब भी 10 फीसद से कम है। एक रपट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

गैर-सरकारी संगठन 'उदैति' की कार्यबल में महिला-पुरुष भागीदारी पर जारी एक रपट के मुताबिक, एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के भीतर महिलाओं का कार्यबल में प्रतिनिधित्व पिछले दो वर्षों से 18 फीसद पर स्थिर है। हालांकि, पिछले वर्ष कुल कार्यबल में छह फीसद की बढ़ोतरी हुई जबकि महिला कर्मचारियों की संख्या सात फीसद बढ़ी। यह दर्शाता है कि महिलाएं कार्यबल में पहले से

गैर-सरकारी संगठन 'उदैति' की कार्यबल में महिला-पुरुष भागीदारी पर जारी एक रपट के मुताबिक, एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के भीतर महिलाओं का कार्यबल में प्रतिनिधित्व पिछले दो वर्षों से 18 फीसद पर स्थिर है। हालांकि, पिछले वर्ष कुल कार्यबल में छह फीसद की बढ़ोतरी हुई जबकि महिला कर्मचारियों की संख्या सात फीसद बढ़ी। यह दर्शाता है कि महिलाएं कार्यबल में पहले से अधिक संख्या में आ रही हैं।

अधिक संख्या में आ रही हैं, लेकिन उनकी आनुपातिक हिस्सेदारी पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रही।

रपट में एनएसई पर सूचीबद्ध 1,386 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें महिला-पुरुष प्रतिनिधित्व, वेतन अंतर, नेतृत्व में समावेश, कार्यस्थल छोड़ने और लौटने की दर जैसे पहलुओं की समीक्षा शामिल है। रपट कहती है कि अस्पतालों और क्लिनिकल लैब में महिलाओं की हिस्सेदारी 45 फीसद से बढ़कर 48 फीसद हो गई है जबकि उपभोक्ता सेवाओं में यह 30 फीसद से बढ़कर 34 फीसद हुई, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी (34 फीसद) और बैंकिंग क्षेत्रों (26 फीसद) में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके साथ ही महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच वेतन का अंतर घटा है। वित्त वर्ष 2023-24 के 6.7 फीसद से मुकाबले यह फासला वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 3.3 फीसद हो गया। हालांकि, कपड़ा, धातु और विविध क्षेत्रों में वेतन अंतर अब भी बड़ा है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर जागरूकता बढ़ी है।

महिला कर्मचारियों के अब खुलकर सामने आने से ऐसी शिकायतें 16 फीसद बढ़ गई हैं। लेकिन लंबित मामलों में 28 प्रतिशत बढ़ोतरी होने से कार्यस्थल पर शिकायतों के निपटान की धीमी रफ्तार भी सामने आती है। उदैति की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पूजा शर्मा गोयल ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार, कंपनियों की लिंग-समर्थ नीतियां और नियोक्ताओं एवं सरकार की निरंतर कार्रवाई महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ा सकती है।

चक्रवात प्रभावित पड़ोसी देश में आपरेशन 'सागर बंधु' जारी

इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में बाढ़ एवं भूस्खलन से 1300 से अधिक लोगों की मौत

बटांग तोरु (इंडोनेशिया), 2 दिसंबर (एपी)।

इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में पिछले सप्ताह आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 1,300 से अधिक हो गई है, जबकि 800 से अधिक लोग लापता हैं। ऐसे में आपातकालीन दल मंगलवार को जीवित बचे लोगों तक पहुंचने और अधिक शवों को निकालने में जुटे रहे। इन देशों में कई दिनों तक भारी बारिश होने से बहुत सारे इलाके जलमग्न हो गये जिससे हजारों लोग फंस गए। कई लोग छतों और पेड़ों पर बैठकर मदद की बाट जोह रहे हैं।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 1,303 लोग मारे गए हैं, जिनमें से इंडोनेशिया में 712, श्रीलंका में 465 और थाईलैंड में 181 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि मृतकों की सही संख्या बताना अभी जल्दबाजी होगी। सबसे अधिक प्रभावित देश इंडोनेशिया में, बचावकर्मियों को सुमात्रा द्वीप के गांवों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जहां सड़कें बह गईं और पुल ढह गए। देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजंसी के अनुसार, कम से कम 507 लोग लापता हैं। हेलिकाप्टर और नावें तैनात की गई हैं, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिगड़ते मौसम और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के कारण बचाव अभियान धीमा पड़ रहा है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने मंगलवार को बताया कि सेना के नेतृत्व वाली बचाव टीम चक्रवात डिटवा के बाद बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में 336 लोगों की तलाश में जुटी हैं, जो अब भी लापता हैं। भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और पुल ढह गए हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल हो गया है। दक्षिणी थाईलैंड में भीषण बाढ़ के बाद सड़कों और इमारतों की सफाई शुरू की गई है। भीषण बाढ़ से 15 लाख से अधिक घर और 39 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

सुमात्रा प्रांत में बाढ़ से प्रभावित इलाके में खोज अभियान चलाता बचाव दल।

श्रीलंका राहत मिशन पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, भारत बोला- चार घंटे में दी मंजूरी

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (ब्यूरो)।

चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की राहत उड़ान को लेकर भारत व पाकिस्तान के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत उसकी मानवीय सहायता वाली उड़ानों को जानबूझकर रोक रहा है, जिससे श्रीलंका तक राहत पहुंचाने में देरी हो रही है। हालांकि, भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि उसने मानवीय दृष्टि से पाकिस्तान के अनुरोध को उसी दिन, सिर्फ चार घंटे के भीतर मंजूरी दे दी थी। भारत ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे भ्रामक दावों को भी सिरे से नकार दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान 'हास्यास्पद' है और यह भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने का एक और प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका की कठिन परिस्थिति में पूरी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयसवाल ने बताया कि पाकिस्तान का औपचारिक अनुरोध एक दिसंबर को दोपहर करीब 13:00 बजे भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद को मिला था। सरकार ने इसे मानवीय आपात स्थिति मानते हुए उसी दिन शाम 17:30 बजे मंजूरी जारी कर दी थी। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में चल रही यह खबर कि भारत ने हवाई क्षेत्र की अनुमति नहीं दी, पूरी तरह झूठी है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया 'फर्जी खबर' फैला रहा है और यह सिर्फ भारत की छवि खराब करने की कोशिश है। अधिकारियों ने कहा कि भारत की नीति मानवीय सहायता को प्राथमिकता देने की है और ऐसे मामलों में राजनीतिक इरादे नहीं रखे जाते। भारत ने यह भी दोहराया कि सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर सिर्फ चार घंटे में मंजूरी दी गई, जो सबसे कम समय में किया गया निर्णय था।

वैभव सूर्यवंशी के नाबाद शतक के बावजूद बिहार को मिली हार

कोलकाता, 2 दिसंबर (भाषा)।

प्रतिभावान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की 61 गेंद में नाबाद 108 रन की पारी के बावजूद बिहार को मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के ग्रुप बी मैच में महाराष्ट्र के खिलाफ तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर बिहार ने 14 साल के सूर्यवंशी की नाबाद पारी से तीन विकेट पर 176 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और सात छक्के मारे और टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इसके जवाब में महाराष्ट्र ने कप्तान पृथ्वी साव की 30 गेंद में 66 रन की पारी के अलावा नीरज जोशी(30), रंजीत निकम (27) और निखिल नाईक (22) की पारियों से पांच गेंद शेष रहते सात विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की।

मोहम्मद इजहार (22 रन पर दो विकेट) और सकीबुल गनी (50 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाकर बिहार को मैच में बनाए रखा, लेकिन महाराष्ट्र ने अंततः धैर्य बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले सूर्यवंशी ने सात छक्के जड़ बिहार की ओर से टी20 पारी में सर्वाधिक छक्कों का रेकार्ड बनाया। उन्होंने आयुष लोहारुका (नाबाद 25) के साथ चौथे विकेट के लिए 75 रन जोड़े। सूर्यवंशी ने अंतिम ओवर में अर्शिन कुलकर्णी पर चौके के साथ शतक पूरा किया।

जाधवपुर यूनिसर्विटी मैदान पर गोवा ने मध्य प्रदेश को सात विकेट से हराया। मध्य प्रदेश के 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा ने सुयश प्रभुदेसाई (नाबाद 75) और अभिनव तेजराणा (55) के अर्धशतक से 18.3 ओवर में तीन विकेट पर171 रन बनाकर जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश ने इससे पहले हरप्रीत सिंह के 80 रन की बदौलत छह विकेट पर 170 रन बनाए।

बड़ौदा ने पंजाब को सात विकेट से हराया

भारतीय हरफनमौला हार्दिक पंड्या ने दो महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए नाबाद 77 रन बनाये जिसकी मदद से बड़ौदा ने सैयद मुश्ताक अली ट्राफी ग्रुप सी के मैच में पंजाब को सात विकेट से हराया। पंड्या ने 42 गेंद में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से यह पारी खेली। पंजाब ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 222 रन बनाए थे जिसमें भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के 19 गेंद में 50 रन शामिल है ।

पंड्या की पारी के दम पर बड़ौदा ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 224 रन बनाए । सितंबर में दुबई में एशिया कप सुपर फोर्स में श्रीलंका के खिलाफ खेलने के बाद पंड्या का यह पहला प्रतिस्पर्धी मैच था। उन्होंने चार ओवर गेंदबाजी करके 52 रन दिए और एक विकेट भी लिया। बड़ौदा इस समय आठ अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है जबकि गुजरात शीर्ष पर और पंजाब दूसरे स्थान पर है। वहीं एक अन्य मैच में गुजरात ने पुदुचेरी को नौ विकेट से हराया।

सैयद मुश्ताक अली ट्राफी

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में सात चौके और सात छक्के मारे और टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। सूर्यवंशी ने सात छक्के जड़ बिहार की ओर से टी20 पारी में सर्वाधिक छक्कों का रेकार्ड बनाया। उन्होंने आयुष लोहारुका (नाबाद 25) के साथ चौथे विकेट के लिए 75 रन जोड़े।

दिल्ली का निराशाजनक प्रदर्शन, त्रिपुरा ने पहली बार हराया

अहमदाबाद, 2 दिसंबर (भाषा)। दिल्ली का मौजूदा घरेलू सत्र में निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा जब मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के ग्रुप डी मैच में आइपीएल खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद उसे त्रिपुरा की कमजोर मानी जाने वाली टीम के खिलाफ पहली बार 12 रन से हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा घरेलू सत्र में रणजी ट्राफी में भी दिल्ली को जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहली बार शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

रणजी ट्राफी में दिल्ली को अपने आखिरी दोनों मैच जीतने के बावजूद नाकआउट में पहुंचने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में भी टीम चार में से दो मैच गंवाकर मुश्किल में है। त्रिपुरा के 158 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों ने धीमी पिच पर निराश किया और मणिशंकर मूरासिंह (दो विकेट) तथा विक्की साहा (दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 145 रन ही बना सके। मूरासिंह ने इससे पहले 18 गेंद में नाबाद 25 रन की पारी भी खेली जिससे त्रिपुरा ने पांच विकेट पर 157 रन बनाए।

Source- दैनिक जागरण

प्रेम कुमार निर्विरोध बने विधानसभा अध्यक्ष

19वें अध्यक्ष का पद संभालने के बाद बोले, सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों मेरे लिए एक समान होंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता और नौ बार के विधायक डा. प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। विधानसभा सचिवालय को प्रेम कुमार के नाम के चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मंगलवार को विधानसभा में पहले प्रस्तावक गृह व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना प्रस्ताव में पेश किया। जिसका अनुमोदन संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। विपक्ष की इस दौरान कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जिसके बाद प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया।

प्रेम कुमार के 19वां विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव उन्हें साथ लेकर आए और आसान पर बिठाया। इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने सदन की कार्यवाही की पूरी जिम्मेदारी डा. प्रेम कुमार को सौंप दी। अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदन के नेता नीतीश कुमार सहित सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने प्रेम कुमार को बधाई दी। पक्ष-विपक्ष ने उम्मीद जताई कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में सदन सुचारू ढंग से चलेगा और सरकार तथा विपक्ष के बीच स्वस्थ तालमेल कायम रहेगा। अपने प्रथम संबोधन में प्रेम कुमार ने गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता ने जिस ऐतिहासिक जनमत देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह संवाद, सहयोग और विकास की राजनीति को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से चयनित होना उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वे पूरी निष्पक्षता और मर्यादा के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को अध्यक्ष के आसन तक लाकर बिठाया। • सौ : वीडियो ग्रैब

मुख्यमंत्री बोले, प्रेम कुमार का अनुभव लंबा

प्रेम कुमार के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा खुशी की बात है कि डा. प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन है। नव निर्वाचित सदस्यों को भी बधाई है। डा. प्रेम कुमार शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। उनका बहुत पास लंबा अनुभव है। सदन के संचालन में अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि नव निर्वाचित अध्यक्ष को खड़ा होकर प्रणाम करें। तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी कहा कि अरे भाई खड़ा होकर प्रणाम करें।

उम्मीद है कि नियमानुसार निभाएंगे जिम्मेदारी : तेजस्वी

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है आसन पर बैठकर डा. प्रेम कुमार नियमों के अनुसार जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। उनका अनुभव मंत्री और विरोधी दल के नेता के रूप में रहा है। ऐसे में किसी को निराश नहीं करेंगे। विपक्ष सरकार का ही अंग होता है। उन्होंने कहा कि आसन की ओर से विपक्ष को उचित समय मिलेगा। इस तरह तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को बधाई देते हुए सदन में एक सकारात्मक और सहयोगात्मक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया।

विस सत्र के दूसरे दिन पांच और सदस्यों ने ली शपथ, दो बचे

विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन सुनील कुमार, जीवेश कुमार, विनय बिहारी, मदन सहनी, केदार नाथ सिंह को शपथ दिलाई गई। इसके साथ अब तक 241 सदस्यों का शपथ ग्रहण हो चुका है। अनंत सिंह और अमरेंद्र पांडेय ही दो सदस्य हैं, जो अब तक शपथ नहीं ले पाए।

अब तक 37,589 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कें हुई चकाचक

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : ग्रामीण परिक्षेत्र में 40265 किलोमीटर लंबाई की कुल 16174 सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का लक्ष्य तय किया गया था। उनमें से अब तक 37589 किलोमीटर लंबाई की 15589 सड़कों को चकाचक किया जा चुका है। यह ग्रामीण कार्य विभाग का दावा है। यह मात्र सड़क नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए बाजार, अस्पताल, स्कूल और रोजगार तक पहुंच के माध्यम से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के अंतर्गत सड़कें दुरुस्त की जा रहीं। सड़कों के विस्तार और उनके चकाचक होने से ग्रामीणों के जीवन-स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। इनमें से सर्वाधिक सड़कों की सूरत पूर्वी चंपारण जिला में बदली हैं। मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इनके अलावा सारण में 1750, समस्तीपुर में 1416, गया में 1412 और वैशाली जिला में 1389 किलोमीटर लंबाई में सड़कों की मरम्मत हुई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली गति, कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में भी ग्रामीण सड़कों की भूमिका महत्वपूर्ण

प्रथम तीन जिले

1. पूर्वी चंपारण : सड़कों की मरम्मत के मामले में पूर्वी चंपारण जिला सबसे आगे है। यहां चयनित कुल 957 सड़कों में 918 की मरम्मत हो चुकी है। उनकी कुल लंबाई 2392 किलोमीटर है।

2. मुजफ्फरपुर : मरम्मत के आधार पर दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर जिला है। यहां की कुल 718 सड़कों में 694 सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। कुल 1861.53 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य है। उसके विरुद्ध 1742.86 किमी लंबाई में मरम्मत हो चुकी है।

3. पश्चिम चंपारण : इस क्रम में पश्चिम चंपारण जिला तीसरे स्थान पर है। यहां कुल 617 ग्रामीण सड़कों को चकाचक करने का लक्ष्य है, जिनकी कुल लंबाई 2091 किमी है। अब तक 2052.82 लंबाई में 604 सड़कों का कायाकल्प किया जा चुका है।

यूजर कभी भी हटा सकेंगे संचार साथी एप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मोबाइल फोन में संचार साथी एप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टाल करने के आदेश का विपक्ष की ओर से मुखर विरोध होने बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यह अनिवार्य नहीं होगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह एप पूरी तरह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है। यूजर्स चाहें तो एप को सक्रिय कर इसका लाभ ले सकते हैं और न चाहें तो वे किसी भी समय इसे अपने फोन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं।

संचार मंत्रालय ने सभी फोन निर्माता कंपनियों को सोमवार को हैंडसेट की बिक्री से पहले उसमें संचार साथी एप अनिवार्य रूप से डालने का निर्देश दिया था। विपक्ष ने संचार साथी एप से लोगों की निगरानी व जासूसी करने का आरोप लगाया है। विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए सिंधिया ने कहा कि एप के जरिये कोई जासूसी या काल मानिटरिंग नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, ''यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस एप को सभी तक पहुंचाएं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट कर दें। अगर आप इसे रजिस्टर करेंगे, तो यह एक्टिव रहेगा। अगर आप इसे रजिस्टर नहीं करेंगे, तो यह इनएक्टिव रहेगा।''

सूत्र ने बताया कि एपल मौजूदा रूप में आदेश को लागू नहीं कर पाएगी। एपल ने भले ही सरकार से चर्चा करने की मंशा व्यक्त की है, लेकिन उसने इस तरह की एक चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंगलवार को बताया कि संचार साथी एप से जुड़े मामलों पर एक वर्किंग ग्रुप में सभी मोबाइल फोन कंपनियों के साथ चर्चा की गई, लेकिन एपल ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।

- विपक्ष ने संचार साथी एप से लोगों की निगरानी व जासूसी करने का लगाया आरोप
- संचार मंत्री ने कहा- यह एप किसी की निगरानी के लिए नहीं लोगों की सुरक्षा के लिए

यह जन भागीदारी की तरफ एक कदम है। जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो संचार साथी एप के जरिये आप जान सकते हैं कि आइएमईआइ नंबर नकली है या असली।

-ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार मंत्री

एप से मिलने वाली सुविधाएं

इस एप पर फोन के चोरी होने पर शिकायत करने और फोन को ब्लाक करवाने की सुविधा है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस चोरी के फोन में सिम डालेगा, उसका अलर्ट पुलिस को व यूजर को आ जाता है। आपके नाम पर कितने सिम जारी हो चुके हैं, इसकी भी जानकारी हासिल करने की सुविधा है। अगर आपकी जानकारी के बगैर सिम कार्ड जारी हुआ है तो आप उसे बंद करवा सकते हैं। इसी सुविधा के जरिये ही 50 लाख कनेक्शन काटे जा चुके हैं।

संबंधित समाचार >> पेज 13

राजभवन नहीं, अब बिहार लोकभवन कहिए

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : बिहार के राजभवन का नाम बदल गया है। केंद्र सरकार के एक निर्णय के तहत अब इसका नाम लोकभवन हो गया है। इस आशय की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंग्थु के हस्ताक्षर से एक दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल बिहार लोकभवन के रूप में नामित किया जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। उसमें कहा गया था कि राज्यों के राजभवन और केंद्र शासित प्रदेशों के राज निवास के नाम बदलकर क्रमशः लोकभवन और लोक निवास किए जाएं। बिहार के राजभवन का नाम परिवर्तन इसी संदर्भ में किया गया है। केंद्र सरकार ने नाम में परिवर्तन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत करने के इरादे से किया है। राजभवन और राज निवास जैसे नाम ब्रिटिश शासनकाल में दिए गए थे। 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार के गठन के साथ ही ब्रिटिश शासन की याद दिलाने वाले संस्थानों और मार्गों के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। यह उसी अभियान की एक कड़ी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। नेम प्लेट और तमाम ऐसे साइन बोर्ड, जहां राजभवन लिखे हुए हैं, बदल कर लोकभवन किए जा रहे हैं। राजभवन के वेबसाइट पर बदलाव हो गया है। अब यह बिहार लोकभवन के नए नाम से है। बिहार में राजभवन की आधारशिला वायसराय लार्ड हार्डिंग ने 1913 में रखी थी। इसके तीन साल बाद तीन फरवरी 1916 को उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया था। उसी दिन पटना हाई कोर्ट और मुख्य सचिवालय भवन का भी उद्घाटन हुआ था। न्यूजीलैंड के जेके मुनीफ इन भवनों के आर्टिटेक्ट थे।

1913 में वायसराय लार्ड हार्डिंग ने बिहार में राजभवन की आधारशिला रखी थी

25 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाम परिवर्तन का जारी किया था आदेश

- केंद्र सरकार के निर्णय के बाद नाम में किया गया परिवर्तन अधिसूचना की गई जारी
- लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मजबूत करने के इरादे से केंद्र ने नाम में किया परिवर्तन

अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार लगातार अव्वल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : सरकारी अस्पतालों की ओपीडी से लेकर भर्ती होने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार यह जानकारी दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट का हवाला देकर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही बिहार ने 79.34 अंकों के साथ राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया था। तब से बिहार लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है। इस वर्ष एक बार फिर अक्टूबर महीने में रोगियों को दवा उपलब्ध कराने में बिहार ने 81.35 अंकों के साथ पहले स्थान का खिताब जीत लिया है। जबकि, 77.77 अंकों के साथ राजस्थान दूसरे और 71.80 अंकों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है। यहां बता दें कि विभाग का दावा है कि दवा और अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए राज्य में फिलहाल जीपीएस से लैस 165 औषधि वाहन चलाए जा रहे हैं। इस पूरी योजना का मकसद राज्य के नागरिकों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराना है।

डेंगू की स्वदेशी वैक्सीन के लिए पटना में हो रहा परीक्षण

अहमद रजा हाशमी ● जागरण

पटना सिटी : डेंगू के उपचार के लिए अब तक कोई विशेष दवा नहीं है। मरीज के शरीर पर होने वाले प्रभाव को देखते हुए चिकित्सक पैरासिटामोल समेत सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। डेंगू के सटीक इलाज के लिए विकसित स्वदेशी वैक्सीन पर अगमकुआं स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आरएमआरआइ) में 18 से 60 वर्ष के स्वस्थ व्यक्तियों पर परीक्षण किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की टीम इस काम में दिन-रात लगी है। दो साल के ट्रायल से आने वाले नतीजों के बाद देश में विकसित डेंगू का वैक्सीन मरीजों के लिए, उपलब्ध हो जाएगा।

आरएमआरआइ के निदेशक और देश के जाने माने वैज्ञानिक डा. कृष्णा पांडेय ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में डेंगू के स्वदेशी वैक्सीन पर परीक्षण पटना समेत देश के 19 केंद्रों पर जारी है। अगमकुआं स्थित केंद्र पर चार सौ स्वस्थ व्यक्तियों पर डेंगू वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। निदेशक ने बताया कि आइसीएमआर के नेतृत्व में नई

आरएमआरआइ में 18 से 60 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति पर हो रहा ट्रायल, नतीजा आते ही मरीजों के लिए उपलब्ध होगी पहली वैक्सीन

राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ● जागरण

दिल्ली के पैनेस बायोटेक द्वारा यह वैक्सीन विकसित किया गया है।

कालाजार के लिए एलएफसई 408 टैबलेट पर ट्रायल : आरएमआरआइ में कालाजार मरीजों के लिए एलएफसई 408 टैबलेट का ट्रायल 105 मरीजों पर किया जा रहा है। निदेशक डा. कृष्णा पांडेय ने बताया कि छह महीनों बाद इसका परिणाम आएगा।

पूर्व में कालाजार के लिए एक कैप्सूल विकसित किया जा चुका है।उन्होंने बताया कि बिहार समेत देश में कालाजार पर नियंत्रण पाया जा चुका है। तीन साल तक इस बीमारी के मरीजों पर नजर रखने की प्रक्रिया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जारी है। 2026 के अंत तक योजना में पूर्ण सफलता मिलते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतिम रूप से भारत को कालाजार मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।

मलेरिया के लिए छह सौ प्रवासी मजदूरों पर परीक्षण जारी : मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए भी आरएमआरआइ में लिए गए छह सौ प्रवासी मजदूरों के नमूनों पर वैज्ञानिकों की टीम जांच व शोध कर रही है। निदेशक ने बताया कि अब तक लगभग दस मजदूरों के नमूनों में जांच उपरांत मलेरिया होने का प्रमाण मिला है। दो हजार मजदूरों पर यह परीक्षण किया जाना है।

मुक्त व्यापार समझौता नीति सही, सात प्रतिशत से ज्यादा रहेगी विकास दर

साक्षात्कार

जयप्रकाश रंजन • जागरण

- फिक्की प्रेसिडेंट अनंत गोयनका ने कहा- भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने के लिए सरकार के साथ मिलकर करेंगे काम
- मजबूत दिख रहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे आधारभूत तत्व, रोजगार के अवसर जल्द बढ़ेंगे

अनंत गोयनका •

नई दिल्ली: इंडिया इंक पूरी तरह से बदला हुआ है। अब उसे दूसरे देशों के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से डर नहीं लगता बल्कि वह इसे एक अवसर के तौर पर देखता है। देश के प्रमुख उद्योग संगठन फिक्की के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट अनंत गोयनका कुछ ऐसा ही मानते हैं। वह मानते हैं कि भारत जिन देशों के साथ वर्तमान में एफटीए पर बातचीत कर रहा है या जिनके साथ समझौते लागू हो चुके हैं, वे समझौते पहले के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक और भारतीय हितों के अनुकूल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन समझौतों से भारतीय उद्योग को स्पष्ट रूप से लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वह मानते हैं कि मौजूदा परिवेश में फिक्की जैसे उद्योग चैंबरों को भी देश की इकोनमी में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए और भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

गोयनका यह भी मानते हैं कि भारत तेज आर्थिक विकास दर के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने दैनिक जागरण को बताया, 'दूसरी तिमाही के दौरान 8.2 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर बहुत उत्साहजनक है। भारतीय अर्थव्यवस्थ के सारे आधारभूत तत्व काफी मजबूत दिख रहे हैं। हमारा राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, महंगाई की दर भी काबू में है। साथ ही सरकार की तरफ से देश में मांग बढ़ाने के लिए जो सुधारवादी कदम उठाए गए हैं वह काफी असर डालेगा। मौजूदा हालात में जब मैं देखता हूं कि देश की इकोनमी के साथ खराब क्या हो सकता है तो बहुत कुछ नहीं दिखता लेकिन जब यह देखता हूं कि अच्छा क्या हो सकता है तो मुझे कई तथ्य दिखाई देते हैं। जैसे अमेरिका के साथ किया जाने वाला एफटीए, इसका बहुत ही अच्छा असर होगा, ब्याज दरों में और कमी की संभावना है। विकास दर को लेकर काफी सकारात्मक हूं। यह सात प्रतिशत से ज्यादा रहेगी।

भारतीय उद्योग जगत को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा

गोयनका ने कहा कि बतौर फिक्की प्रेसिडेंट वह मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर सरकार की नीतियों और उद्योग जगत के बीच सामंजस्य बनाने पर काफी ध्यान देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भारतीय उद्योग जगत को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था, वैसा नहीं दिया गया है। गोयनका ने कहा, 'यह फिक्की का एक मुख्य काम होगा ताकि हम हर तरह से भारत के कुल जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की मौजदा हिस्सेदारी 15-16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक कर सकें। उद्देश्य यह रहेगा कि भारत को दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर स्थापित किया जा सके। यह निश्चित तौर पर होगा।' यह पूछे जाने पर कि भारत मैन्यूफैक्चरिंग में एक बड़ी शक्ति क्यों नहीं बन पाया तो गोयनका ने इसके लिए भारतीय उद्योग जगत को जिम्मेदार ठहराया। उनका जवाब था, 'भारतीय उद्योग जगत को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अभी सौ की मांग है तो हम सौ का उत्पादन ही करने पर ध्यान दे रहे हैं जबकि चीन की कंपनियां 300 यूनिट उत्पादन का प्लांट लगाने की सोचते हैं।'

अब ज्यादा व्यापक है भारत का एफटीए ढांचा

फिक्की के नए प्रेसिडेंट ने कई वैश्विक आर्थिक शक्तियों के साथ एफटीए करने की भारत सरकार की कोशिश का पूरा समर्थन किया। पूर्व में जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के साथ एफटीए का भारत को पूरा फायदा नहीं होने के बावजूद उनका मानना है कि अब हालात बदल गए हैं। गोयनका ने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत का एफटीए का ढांचा अब ज्यादा व्यापक है लेकिन साथ ही पूरी दुनिया का स्वरूप भी बदला है। आस्ट्रेलिया, यूएई के साथ जो एफटीए हुआ है उसका सकारात्मक असर भारतीय कारोबार पर दिख रहा है। हमें उम्मीद है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ होने वाले एफटीए का और ज्यादा सकारात्मक असर भारतीय उद्योग पर होगा। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी और जो भी समझौता होगा वह पूरे देश के लिए सही होगा।

इंट्रा-डे में पहली बार 90 के स्तर पर पहुंचा रुपया

अंत में 43 पैसे टूट सबसे निचले स्तर 89.96 प्रति डालर पर बंद हुई भारतीय मुद्रा

मुंबई, प्रेट्र: दिन के कारोबार के दौरान मंगलवार को पहली बार डालर के मुकाबले रुपया 90 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, दिन के अंत में भारतीय मुद्रा 43 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 89.96 प्रति डालर पर बंद हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि सटोरियों द्वारा अपना सौदा पूरा करने के लिए लगातार डालर की खरीदारी और आयातकों की डालर को लेकर मांग बनी रहने से रुपया नीचे आया है। इसके साथ ही विदेशी पूंजी की निकासी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता जैसे कई दबावों के कारण निवेशकों की धारणा कमजोर बनी हुई है।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.70 प्रति डालर पर खुला। कारोबार के दौरान एक समय यह 47 पैसे टूटकर डालर के मुकाबले 90.00 के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में यह डालर के मुकाबले 89.96 के रिकार्ड निचले स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 43 पैसे की गिरावट को दर्शाता है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डालर की स्थिति को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.41 पर रहा।

कोटक सिक्योरिटीज के जिंस एवं मुद्रा प्रमुख अनिंद्य बनर्जी का कहना है कि डालर के मुकाबले रुपये का 90 पर पहुंचना एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक स्तर है। यदि रुपया इससे ऊपर जाता है, तो बाजार तेजी से 91.00 या उससे भी अधिक के उच्च प्रवृत्ति वाले चरण में स्थानांतरित हो सकता है। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक को रुपये को 90 से नीचे बनाए रखने के लिए सक्रिय रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस स्तर पर केंद्रीय बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह सट्टेबाजों पर लगाम लगाए, क्योंकि इससे डालर और रुपये के बीच पैदा होने वाली अस्थिरता में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

गिरावट की प्रमुख वजह

- सटोरियों द्वारा लगातार डालर की खरीदारी और आयातकों की मांग बने रहना
- विदेशी निकासी और भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देरी से धारणा कमजोर होना

47 पैसे तक टूटी भारतीय मुद्रा डालर के मुकाबले दिनभर के कारोबार में

99.41 प्रतिशत पर पहुंचा डालर की स्थिति को दर्शाने वाला सूचकांक

अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने पर रुपया होगा मजबूत

नई दिल्ली, एएनआइ: क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो जाता है तो लगातार गिर रहा रुपया एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि, यह काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वैश्विक वित्तीय हालात किस तरह करवट लेते हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाले में महीनों में रुपया इस स्तर से और मजबूत होगा। उन्होंने कहा, 'अगर आप 2013-14 से रुपये का इतिहास देखें तो हमने ऐसे समय भी देखे हैं जब रुपया बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। ऐसा समय भी आया है जब यह मजबूत हुआ है। कमोवेश यह कहना ज्यादा ठीक है कि रुपये का कमजोर होना और मजबूत होना बाजार के हालात का हिस्सा है।

बैंक शेयरों में बिक्री से सेंसेक्स 504 अंक गिरा

मुंबई, प्रेट्र: मंगलवार को ब्लू चिप बैंक स्टाक व रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिकवाली और लगातार विदेशी फंड की निकासी से सेंसेक्स करीब 504 अंक गिर गया। 30 शेयरों वाला बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 503.63 अंक या 0.59 प्रतिशत गिरकर 85,138.27 पर बंद हुआ। दिन के दौरान एक समय यह 588.9 अंक गिरकर 85,053 के निचले स्तर पर आ गया था। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 143.55 अंक या 0.55 प्रतिशत गिरकर 26,032.20 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आइसीआइसीआइ बैंक, भारत इलेक्ट्रानिक्स और लार्सन एंड टूब्रो सबसे ज्यादा पिछड़े। हालांकि, एशियन पेंट्स, मारुति, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस फायदे में रहे।

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत तापसे ने कहा कि एफआइआइ की बिकवाली एक बार फिर से तेज हो गई है और पिछले तीन कारोबारी दिनों में 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घरेलू शेयर बेचे हैं।

अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय

- 'राजभवन कहे जाएंगे 'लोकभवन', केंद्रीय सचिवालय की जगह 'कर्तव्य भवन' ने ली
- पीएम मोदी की जनता में 'अपनी सरकार' की भावना और आत्मविश्वास जगाने की पहल

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को समाहित करने वाला नया परिसर अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत तैयार हो रहा यह परिसर अपने अंतिम चरण में है और पहले 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के नाम से जाना जाता था।

सेवा तीर्थ के नए परिसर में पीएमओ के साथ कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और 'इंडिया हाउस' भी शामिल होंगे, जहां विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक होगी। अधिकारियों का कहना है कि 'सेवा तीर्थ' केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि सेवा-भाव और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया कार्यस्थल होगा। उन्होंने कहा कि शासन का विचार सत्ता से सेवा और अधिकार से जवाबदेही की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव सिर्फ संरचनात्मक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक भी है। गौरतलब है कि पीएम का आधिकारिक निवास भी रेस कोर्स रोड कहलाता था, जिसे 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। 'राजपथ' का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' किया गया था, जबकि केंद्रीय सचिवालय को 'कर्तव्य भवन' नाम दिया गया है, जो सार्वजनिक सेवा के संकल्प का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों आठ राज्यों में राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय का कहना था कि 'राज भवन' औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए राज्यपालों और उप-राज्यपालों के कार्यालयों को अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा के राज भवनों के नाम बदले गए हैं। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल के निवास-कार्यालय को अब लोक निवास कहा जाएगा। इसे पहले राज निवास कहा जाता था। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शासन से जुड़े स्थलों को 'कर्तव्य' और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नया रूप दिया जा रहा है। ये भारत को उसकी औपनिवेशिक जड़ों से मुक्त करने के प्रयासों का हिस्सा है। भारत अपने लोकतंत्र को नई भाषा दे रहा है- जहां शक्ति नहीं, जनता केंद्र में है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से गहरे देश में नाम बदलना सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिकता में बदलाव की शुरुआत है।

छोटा बदलाव और बड़ा संदेश

पहले	अब
राज पथ	कर्तव्य पथ
प्रधानमंत्री आवास	लोक कल्याण मार्ग
केंद्रीय सचिवालय	कर्तव्य भवन
राज भवन	लोक भवन
पीएमओ	सेवा तीर्थ

कार्यालय जाते पीएम नरेन्द्र मोदी। ● प्रेट्र

पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता का नहीं, बल्कि सेवा का पर्याय बन गई है, जिसमें सरकार का सर्वोच्च नेता खुद को प्रधान सेवक मानता है और लोगों के लिए सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे काम करता है। - **अमित शाह**, केंद्रीय गृह मंत्री

वनडे करियर बढ़ाने के लिए 15 साल बाद विजय हजारे ट्राफी खेलेंगे विराट

दिल्ली के शुरुआती दो से तीन मैच खेलेंगे विराट रोहित भी मुंबई की ओर से खेलेंगे

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

नई दिल्ली: टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके विराट कोहली अपना वनडे करियर आगे बढ़ाने के लिए 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्राफी में दिल्ली के लिए खेलेंगे। विराट अंतिम बार 2010 में इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट में खेले थे। अब सिर्फ एक प्रारूप में खेल रहे विराट को अपने वनडे करियर को बढ़ाने के लिए विजय हजारे ट्राफी में खेलने को मजबूर होना पड़ा है। विराट जब अंतिम बार विजय हजारे ट्राफी में खेले थे, तब उस मैच में बीसीसीआइ के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने शतक लगाया था।

रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए मौजूद विराट ने डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली को फोन कर दिल्ली की ओर से खेलने की जानकारी दी। दिल्ली का पहला मैच 24 दिसंबर को बेंगलुरु या अलूर में आंध्र प्रदेश से होगा। सूत्रों के अनुसार, विराट दिल्ली की ओर से तीन या चार मुकाबले खेलेंगे। दिल्ली का दूसरा मैच 26 दिसंबर को गुजरात और 29 दिसंबर को सौराष्ट्र से होगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि विराट के हां करने के बाद ये मैच अलूर में होंगे या बेंगलुरु में। सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा भी मुंबई के लिए विजय हजारे ट्राफी में कुछ मैच खेलेंगे।

'दैनिक जागरण' ने पहले ही बताया था कि आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे सीरीज के बाद अगर विराट और रोहित को अपना वनडे करियर आगे बढ़ाना है तो उन्हें इस प्रारूप में होने वाली घरेलू सीरीज में खेलना होगा। मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर भी चाहते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट में खेलें।

रांची में पहले वनडे मैच के बाद एयरपोर्ट पर चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा ने लंबे समय तक विराट से बात की थी। रांची में ओझा ने रोहित से भी बात की थी। दरअसल, ड्रेसिंग रूम के गरमाए माहौल के बीच रोहित की अगरकर से बात नहीं हो रही है और ऐसा ही कुछ मामला विराट और गंभीर के बीच है। प्रज्ञान दोनों के साथ क्रिकेट खेले हैं और दोनों के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्हें इन दोनों से बात करने के लिए भेजा गया था। रोहित अंतिम बार विजय हजारे ट्राफी में 2018 में खेले थे।

दरअसल, बीसीसीआइ का रुख स्पष्ट है कि भारतीय टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय टीम की ओर से नहीं खेल रहे हैं तो उनके लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। पिछले वर्ष विराट कोहली ने दिल्ली की ओर से रणजी ट्राफी मैच खेला था। रोहित को भी रणजी मैच खेलना पड़ा था। हालांकि इसके बाद दोनों को टेस्ट से संन्यास के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले विराट ने 2012 में यूपी के विरुद्ध दिल्ली की ओर से रणजी ट्राफी मैच खेला था।

विराट कोहली ● फाइल फोटो, प्रेट्र

2027 विश्व कप तक खेलने की क्षमता : शर्मा

विकास मिश्र ● जागरण

राजकुमार शर्मा ● जागरण

लखनऊ : विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा कि विराट 2027 वनडे विश्व कप तक खेलने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस और फार्म बेहतरीन है। वह दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर हैं। कोहली अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी फिटनेस और ग्राउंड पर युवा खिलाड़ी की तरह फील्डिंग करने की क्षमता उन्हें अगले वनडे विश्व कप तक खेलने के लिए सक्षम बनाती है। देश और उनके प्रशंसक भी यही चाहते हैं। कोहली की निरंतरता को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि वह अभी देश के लिए ऐसे ही अपने शतक से भारत को जीत दिलाते रहेंगे। असम टीम के कोच व मेंटर राजकुमार से जब पूछा गया कि क्या विराट अगले वनडे विश्व कप में भारत की जर्सी में दिखेंगे तो उन्होंने कहा, विराट कोहली की फिटनेस उन्हें रुकने नहीं दे रही है। वह अभी भी एक युवा क्रिकेटर की तरह शानदार बल्लेबाजी करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उनकी शतकीय पारी उदाहरण है। मैं विराट को बचपन से जानता हूं। उनमें अभी भी रन की भूख है और यही उनकी सफलता का राज है। राजकुमार ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि वह अगले विश्व कप में टीम का हिस्सा हो और भारत चैंपियन बने, यह सिर्फ मैं नहीं, बल्कि पूरा देश चाहता है। मुझे लगता है कि वह अपने खेल को बखूबी समझते हैं।

यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस लड़ने को तैयार

मास्को, रायटर : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोपीय देशों से युद्ध नहीं चाहता लेकिन यूरोप अगर लड़ना चाहता है तो मास्को युद्ध के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ युद्धविराम के लिए चल रही प्रक्रिया में यूरोपीय देश आए दिन गतिरोध पैदा करने वाली मांगें उठा रहे हैं, रूस को ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के यूरोपीय दौरे के बीच पुतिन ने यह बात प्रेस कान्फ्रेंस कर कही है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकाफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेन में युद्धविराम के लिए प्रस्तावित अमेरिका की शांति योजना पर वार्ता के लिए मास्को पहुंचे हैं। पहले उनकी वार्ता रूसी वार्ताकार किरिल दिमित्रिएव से हुई, उसके बाद वे क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मिले।

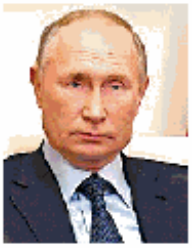

व्लादिमीर पुतिन ● रायटर

गया में 20 हजार श्रद्धालुओं ने की विश्व शांति की कामना

समारोह में उपस्थित लाइट आफ बुद्धा धर्म फाउंडेशन के आंग्चो डिक्सी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अन्य ● जागरण

संवाद सूत्र, जागरण ● बोधगया (गयाजी): विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में मंगलवार को 22वें त्रिपिटक पाठ (चैंटिंग) समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन, महाराष्ट्र के प्रधान सचिव डा. हर्षदीप कांबले और अभिनेता गगन मालिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

पवित्र बोधिवृक्ष के नीचे आयोजित कार्यक्रम में 22 देशों और 17 संघों के लगभग 20 हजार श्रद्धालुओं ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध को नमन कर विश्व शांति की कामना की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बुद्ध के विचार दुनिया का मार्गदर्शन करने में सहायक है।

त्रिपिटक पाठ समारोह

लाइट आफ बुद्धा धर्म फाउंडेशन के आंग्चो डिक्सी ने खाद्य और बुद्ध की मूर्ति देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। शेखावत ने कहा कि उन्हें यहां आकर अपार हर्ष हो रहा है। उन्होंने कहा कि बुद्ध के विचारों में सबसे बड़ा धम्म उदारता है, जो मानवता को बदलने और दुनिया के विचारों को मार्गदर्शन करने में सहायक रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश साझा करते हुए कहा कि त्रिपिटक पाठ समारोह में भाग लेने वाले श्रद्धालु सौभाग्यशाली हैं। भारत का उद्देश्य बौद्ध विरासत को पुनर्स्थापित करना और वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान स्थापित करना है।

दासता के प्रतीकों से मुक्ति आवश्यक

ए. सूर्यप्रकाश

मैकाले ने अंग्रेजी और अंग्रेजियत को श्रेष्ठताबोध के रूप में स्थापित करने का जो अभियान छेड़ा, उसने भारत का बहुत अहित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति में उन्होंने पांच प्रण लेने का आह्वान भी किया है। इनमें एक प्रण औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाना भी है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि अगले दस वर्षों के भीतर थामस बाबिंगटन मैकाले की विरासत को तिलांजलि देनी होगी। असल में मैकाले कुछ और नहीं, बल्कि अंग्रेजियत का एक प्रतीक है। इसी प्रतीक से मुक्ति पाने की प्रधानमंत्री हाल में दो बार चर्चा भी कर चुके हैं। यहां तक कि अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी उन्होंने इस संकल्प का उल्लेख किया।

मैकाले अंग्रेजी राज में सार्वजनिक शिक्षा के निदेशक थे। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं, संस्कृति और सभ्यता की शक्तियों को नष्ट करने के लिए मैकाले ने 1835 में एक विस्तृत योजना बनाई। ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के बाद इस योजना के तहत देशभर में कान्वेंट स्कूलों की बाढ़ आ गई और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा उपेक्षित होती गई। मैकाले की रणनीति कई पहलुओं पर केंद्रित थी। उनका कहना था कि संस्कृत एक 'व्यर्थ' की भाषा है और इसे छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि यह एक श्रेष्ठ सभ्यता की भाषा है और विज्ञान, इतिहास, दर्शन आदि में आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। मैकाले के अनुसार भारतीय भाषाओं में 'न तो साहित्यिक और न ही वैज्ञानिक जानकारी' है और वे 'दरिद्र और अशिष्ट' हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत और अरबी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि 'किसी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक बुक शेल्फ भारत और अरब के समस्त स्थानीय साहित्य से अधिक मूल्यवान है।'

मैकाले का मानना था कि संस्कृत में उपलब्ध पुस्तकों से एकत्रित पैतिहासिक जानकारी इंग्लैंड के प्राथमिक स्कूलों की मामूली सामग्री के समक्ष भी कहीं नहीं ठहरती। स्पष्ट है कि उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि भारतीयों ने शून्य की खोज की थी। भारत में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे अद्भुत गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। वह भी तब, जब ब्रिटिश गुफाओं में रहने और जंगली जानवरों के शिकार पर आश्रित थे। आर्यभट्ट अपनी ज्यामिति, त्रिकोणमिति के अलावा पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों के व्यास की सटीक गणना के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने 1,500 साल पहले की थी। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहणों की व्याख्या की और वर्ष में 365 दिनों

अवनीश रंजन

की संख्या का सटीक आकलन किया। भास्कराचार्य दिग्गज गणितज्ञ थे। उनके आविष्कारों में कलन (कैलकुलस) और ग्रहों की अंडाकार कक्षा शामिल थी, जो उन्होंने 900 साल पहले की थी। मैकाले जैसा अज्ञानी ही इन उपलब्धियों को अनदेखा कर सकता था।

मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी रंग में रंगने का एक सुनियोजित अभियान चलाया। उनकी रणनीति यह थी कि हमें ऐसे लोगों का वर्ग तैयार करना है, जो मूल रूप से तो भले ही भारतीय हों, लेकिन उनके रंग-ढंग पूरी तरह अंग्रेजों जैसे हों। उन्होंने अंग्रेजी और अंग्रेज संस्कृति को श्रेष्ठताबोध के रूप में स्थापित करने का अभियान छेड़ा। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के अभियान को परवान चढ़ाने के लिए मार्च 1835 में एक आदेश जारी किया कि सरकारी धन का उपयोग केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हालांकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों ने कभी नहीं समझा कि पढ़ाई के जरिये किस तरह उनका ब्रेनवाश किया जा रहा है। बेंगलुरु में स्कूली शिक्षा के दौरान मुझे खुद इसकी अनुभूति हुई। जैसे समूचा पाठ्यक्रम अंग्रेजियत पर केंद्रित होता था और पूरा परिवेश भी इंग्लैंड के किसी स्कूल सरीखा था। वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर के आरंभ में होती थीं। इसके बाद एक महीने की क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टी होती थी। सभी छात्रों ने क्रिसमस कैरोल सीखे। जबकि हमारी मातृभाषा कन्नड़ थी, लेकिन स्कूल में कोई कन्नड़ नहीं बोलता था। हमारे इतिहास और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में रामायण, महाभारत या भारत के महान ग्रंथों और गाथाओं का कभी कोई उल्लेख नहीं होता था, लेकिन हमें रोम के निर्माण और जुड़वां भाई रोमुलस और रेमस के बारे में जरूर बताया जाता था। हमें अर्जुन के शौर्य या उनके गांडीव या भीम के कौशल के बारे में कभी नहीं बताया गया, मगर किंग आर्थर और उसकी जादुई तलवार एक्सकैलिबर के किस्से खूब सुनाए जाते थे।

समय का फेर देखिए कि अंग्रेजियत में रंगे ये अधिकांश बच्चे ही कालांतर में प्रमुख पदों पर कमान संभालते गए। राजनीति से लेकर शासन, प्रशासनिक सेवाओं से लेकर मीडिया में उनका ही वर्चस्व स्थापित होता गया। आकांक्षी शहरी वर्ग मैकाले के इस सब्जबाग में फंसता गया, जिसने इसे एक अच्छी जीवनशैली का आधार समझा। एक तरह से वे भारतीय सभ्यता की स्मृतियों को दफन करने की साजिश में षड्यंत्रकारी ही बन गए। मैं भाग्यशाली रहा कि बाद में एक 'भारतीय' स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला, जहां स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, महाभारत और रामायण आदि के संपर्क में आया। यह भी कम दुख की बात नहीं कि स्वतंत्रता के बाद अधिकांश समय सत्ता पर काबिज रहे कांग्रेस और नेहरूवादी और कम्युनिस्टों ने मैकाले के मानस पुत्रों को ही बढ़ावा दिया, जिन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति की निंदा करते हुए फर्जी पंथनिरपेक्ष आख्यान गढ़ा।

भारत को अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने के लिए 2014 में नरेन्द्र मोदी के सतारूढ़ होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। दुख की बात है कि मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने मैकाले की मंशा के विध्वंसकारी प्रभावों का आकलन तक नहीं किया। अब जब मोदी ने इस भयानक समस्या की पहचान की है, तो भारत से प्रेम करने वाले सभी भारतीयों को यह संकल्प लेना चाहिए कि अगले दस वर्षों में मैकाले के प्रेत से पूरी तरह मुक्ति पाई जाए और भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति का अपेक्षित महिमामंडन हो।

(लेखक प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

प्रदेश में चौथे नंबर पर पहुंची मानसिक मंदता दिव्यांगता

जासं, पटना : प्रदेश में दिव्यांगता का स्वरूप बदल रहा है और बढ़ते आंकड़े सरकार व समाज की चिंता बढ़ा रहे हैं। 2011 की जनगणना में करीब 3.69 लाख मामलों के साथ मानसिक मंदता राज्य में चौथे नंबर की सबसे बड़ी दिव्यांगता थी। 14 वर्षों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल की चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। 2011 की जनगणना में प्रदेश में कुल दिव्यांग जनसंख्या करीब 23 लाख थी जो अब बढ़कर 40 लाख हो गई है। इसमें नेत्र के बाद मानसिक मंदता को दूसरे नंबर पर माना जा रहा है। इसका कारण विशेषज्ञ देर से निदान, गर्भावस्था में कुपोषण, प्रसवकालीन जटिलताएं, बच्चों में न्यूरोलाजिकल रोग, संक्रमण और शुरुआती उपचार की कमी को मानते हैं। सबसे चिंताजनक यह है कि जन्म के बाद बच्चों के परीक्षण के लिए मनोचिकित्सक नहीं हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ इसे समय के साथ ठीक हो जाएगा मानकर अनदेखी कर देते हैं। प्रदेश में मानसिक मंदता के अधिसंख्य मामलों की पहचान स्कूलों में होती है। दिव्यांगता की विकराल होती समस्या से निपटने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से इनकी श्रेणियां सात से बढ़ाकर 21 कर दी गईं। प्रदेश में वर्तमान में 40 लाख से अधिक दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार दर्जनों योजनाएं व कार्यक्रम चला रही है। इसके लिए 2 अप्रैल 2018 में समाज कल्याण विभाग के तहत नवीन निदेशालय के रूप में दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय बनाया गया। नई उद्यमी योजना, छात्रवृत्ति, आसरा गृहों के संचालन व यूडीआइडी कार्ड जैसी सुविधाओं ने आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी को मजबूत आधार दिया। सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण जैसी पहल ने इनके अधिकारों व मुख्यधारा में प्रतिनिधित्व को नई ऊंचाई प्रदान की।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर विशेष

40 लाख दिव्यांग हैं वर्तमान में, 2011 की जनगणना में 23 लाख 31 हजार 9 दिव्यांग थे

दिव्यांगता के प्रकार	संख्या
देख नहीं पाने वाले	5,49,080
सुनने में अक्षम	5,72,163
बोलने में अक्षम	4,31,728
चलने-फिरने में अक्षम	1,70,845
मानसिक मंदता	3,69,577
मानसिक बीमारी	89,251
एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता	37,521
अन्य प्रकार की दिव्यांगता	1,10,844

नोट : सभी आंकड़े 2011 जनगणना के आधार पर, उस समय कुल 23 लाख 31 हजार 9 दिव्यांगजन थे।

3,69,577

मानसिक मंदता दिव्यांग थे 2011 में, 14 वर्ष में तेजी से बढ़ी इनकी संख्या

5,49,080

सर्वाधिक दिव्यांग थे नहीं देख पाने वाले, जन्मजात कारणों से इनकी बढ़ी संख्या